भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 3045
उत्तर दिनांक 19/03/2026 को दिया गया

परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता का विस्तार

3045. श्री प्रदीप कुमार वर्मा

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) देश में वर्तमान में परमाणु ऊर्जा की कुल संस्थापित क्षमता कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से कुल कितना ऊर्जा उत्पादन किया गया;

(ग) निर्माणाधीन नई परमाणु परियोजनाओं की संख्या कितनी है; और

(घ) आगामी वर्षों के दौरान परमाणु ऊर्जा क्षमता विस्तार के लक्ष्य क्या हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) देश में, वर्तमान संस्थापित नाभिकीय विद्युत क्षमता 24 नाभिकीय विद्युत संयंत्रों (आरएपीएस-1 – 100 मेगावाट को छोड़कर) को मिलाकर 8,780 मेगावाट है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान नाभिकीय विद्युत संयंत्रों से कुल उत्पादन वर्ष 2022-23 में 45855 मिलियन यूनिट (एमयू), वर्ष 2023-24 में 47971 मिलियन यूनिट और वर्ष 2024-25 में 56681 मिलियन यूनिट रहा।

(ग) व (घ) वर्तमान में, 13600 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 18 नाभिकीय विद्युत रिएक्टर कार्यान्वयनाधीन हैं, जिनमें से 10 नाभिकीय रिएक्टर (पीएफबीआर-500 मेगावाट सहित) निर्माणाधीन हैं और 8 रिएक्टर पूर्व-परियोजना गतिविधियों के अधीन हैं।

स्थान	**परियोजना**	**क्षमता (मेगावाट)**
निर्माण / कमीशनन के अधीन परियोजनाएं		
राजस्थान	आरएपीपी-8	700
कुडनकुलम, तमिलनाडु	केकेएनपीपी-3 व 4	2 X 1000
	केकेएनपीपी-5 व 6	2 X 1000
गोरखपुर, हरियाणा	जीएचएवीपी- 1 व 2	2 X 700
कैगा, कर्नाटक	कैगा-5 व 6	2 X 700
पीएफबीआर, कल्पाक्कम	पीएफबीआर	1 X 500

पूर्व-परियोजना गतिविधियों के अधीन परियोजनाएं		
गोरखपुर, हरियाणा	जीएचएवीपी-3 व 4	2 X 700
चुटका, मध्य प्रदेश	चुटका-1 व 2	2 X 700
माही बांसवाड़ा, राजस्थान	माही बांसवाड़ा-1 व 2	2 X 700
	माही बांसवाड़ा-3 व 4	2 X 700

भाविनि वर्तमान में कल्पाक्कम, तमिलनाडु में 500 मेगावाट(वि) प्रोटोटाइप द्रुत प्रजनक रिएक्टर (पीएफबीआर) परियोजना के कमीशनन का कार्य कर रहा है। सरकार ने कल्पाक्कम, तमिलनाडु में एफबीआर 1 व 2 परियोजना की 2 x 500 मेगावाट(वि) की द्वि-इकाई के लिए पूर्व-परियोजना गतिविधियाँ संचालित करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है। पीएफबीआर की प्रथम क्रांतिकता प्राप्त होने पर, एफबीआर 1 व 2 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति के लिए सरकार से अनुरोध किया जाएगा।

*****